दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, मंगलवार 07 अप्रैल 2020 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 187

महत्वपूर्ण एवं खास

अब देश में कोरोना मरीजों की संख्या 4 हजार 67

» अभी 109 की मौत

नईदिल्ली (आरएनएस)। देश के विभिन्न राज्यों में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस (कोविड 19) के 693 नए मामले सामने आने के कारण इससे संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4067 हो गई तथा इससे 32 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 109 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार की सुबह जारी रिपोर्ट के मुताबिक नये मामले पिछले 24 घंटे के दौरान का है। इस दौरान महाराष्ट्र में सबसे अधिक 200 नये लोग संक्रमित हुए तथा 21 और लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक इस संक्रमण से 292 लोग ठीक हुए हैं। देश में कोरोना से महाराष्ट्र में सर्वाधिक 690 लोग संक्रमित हैं तथा 45 लोगों की मौत हो गयी है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है जहां 571 लोग इससे पीड़ित हुए हैं और पांच लोगों की मौत हुयी है। इसके बाद दिल्ली में सबसे अधिक 503 लोग संक्रमित हैं और सात लोगों की मौत हुयी है। तेलंगाना में अबतक 321 लोग संक्रमित हुए हैं और सात लोगों की मौत हुयी है। केरल में 314 लोग संक्रमित हुए हैं और दो लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में 253 लोग संक्रमण के शिकार हैं लेकिन अब तक किसी की मौत नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में 227 लोग संक्रमित हैं और दो लोगों की मौत हुयी है। आंध्र प्रदेश में 226 और कर्नाटक में 151 लोग संक्रमित हैं तथा क्रमशः तीन और चार लोगों की मौत हुई है। जम्मू-कश्मीर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 106 हो गयी है और दो लोगों की मौत हुयी है। मध्य प्रदेश में 165 और गुजरात में 122 लोग संक्रमित हैं तथा क्रमशः नौ और 11 लोगों की मौत हुई है। पंजाब में छह, पश्चिम बंगाल में तीन तथा बिहार, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है।

डॉक्टरों ने मांगी पीपीई किट, मास्क और सेनेटाइजर

नईदिल्ली (आरएनएस)। कोरोना पीड़ितों का इलाज कर रहे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है. अस्पताल में मांग के अनुसार पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई किट), मास्क और सेनेटाइजर की सप्लाई नहीं होने के चलते अब रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने एक पत्र जारी कर डोनेशन की मांग की है. इस पत्र के अनुसार कोरोना से लड़ने के लिए चिकित्सकों के साथ ही अन्य मेडिकल स्टाफ के लिए करीब 50 हजार पीपीई किट, 50 हजार एन 95 मास्क, 3 लाख ट्रिपल लेयर मास्क और करीब 10 हजार सेनेटाइजर बोतल (500 एमएल) की जरूरत है।

आतिशबाजी के चलते राजधानी में हवा हुई दूषित

नईदिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मददेनजर देशव्यापी लॉकडॉउन की घोषणा के बाद से देश की राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार आने से वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहतर हो गया था लेकिन बीती रात हुई आतिशबाजी के कारण फिर हवा की गुणवत्ता कमतर हो गई है। सिस्टम ऑफ एयर चालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सफर के अध्ययन के अनुसारए राष्ट्रीय राजधानी की हवा की गुणवत्ता-बढ़िया-की श्रेणी से फिसलकर -संतोषप्रद-की श्रेणी में आ गई है। सफर के अनुसार, दिल्ली में सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 87 था और वायु के प्रमुख घटक पीएम-10 और पीएम-2.5 क्रमशः 87 और 47 पाए गए। लेकिन बीती रात दिल्ली-एनसीआर में हुई आतिषबाजी के बाद वायु की गुणत्ता में कमी आ गई। बता दें कि कोरोनावायरस के खिलाफ छिड़ी जंग में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से रविवार की रात नौ बजे घरों के बत्तियां बुझाकर दीये जलाने की अपील की थी जोकि कोरोना जैसी महामारी को मात देने का जज्बा पैदा करने की दिशा में एक कोशिश थी और पूरे देश में लोगों ने प्रधानमंत्री की अपील पर बीती रात नौ बजे दीये जलाकर एकजुटता दिखाई और लोगों ने दिवाली के उत्सव का रूप दे दिया और आतिशबाजी भी की। सफर के अनुसार, लॉकडाउन के दौरान हवा के कण पीएम-2.5 दिल्ली में 49 फीसदी तक घट गई थी।

सांसदों-मंत्रियों के वेतन कटे-दो साल की सांसद निधि भी निरस्त

» पीएम की पहल पर कैबिनेट में हुआ फैसला » अध्यादेश के बाद संसद से सरकार लेगी मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने केलिए मोदी सरकार ने सोमवार को दो अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने संसद के दोनों सदनों के सांसदों का एक साल तक 30 फीसदी वेतन काटने और अगले साल तक सांसद विकास निधि फंड को स्थगित करने का फैसला लिया है। इस फैसले के दायरे में पीएम समेत सभी केंद्रीय मंत्री भी आएंगे।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों ने स्वेच्छा से एक साल तक 30 फीसदी कम वेतन लेने का फैसला किया है। पहली बार वीडियो कांफ्रेंस के

जरिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इन दोनों ही फैसलों पर तत्काल अमल के लिए अध्यादेश लाया जाएगा। इसके बाद आगामी मानसून सत्र में इसे कानून बना कर संसद से पारित करा लिया जाएगा। ये रकम कोरोना के खिलाफ जारी जंग में लगाई जाएगी। जावड़ेकर ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों ने पहले ही स्वेच्छा से एक साल तक अपने वेतन का 30 फीसदी हिस्सा कोरोना से निपटने के लिए दान देने का फैसला किया है। गौरतलब है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को सांसद स्थानीय विकास निधि फंड के तहत प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये मिलते हैं। दो वर्ष का निधि स्थगित होने के कारण एक सांसद के हिस्से का 10 करोड़ रुपये कोरोना फंड में जाएगा। इस प्रकार सिर्फ इसी एक फैसले से 793 सांसदों के हिस्से की करीब 7900 करोड़ की रकम कोरोना फंड में आ जाएगी।

मंत्रालयों को अहम जिम्मेदारी

बैठक में पीएम ने सभी मंत्रियों को लॉकडाउन के बाद की स्थिति को ले कर सतर्क किया। लॉकडाउन के बाद में स्थिति को संभालने के लिए सभी मंत्रालय दस बड़े फैसलों की सूची बना कर उस पर अमल की रणनीति तैयार करें। इसके अलावा मंत्रालय जरूरत वाले 10 इलाकों की भी सूची तैयार करें। इस दौरान उन्होंने मंत्रियों से कोरोना के खिलाफ की जा रही तैयारियों पर चर्चा की।

आपात स्थिति के लिए तैयार हुए 4000 आइसोलेशन बिस्तर

» रेलवे ने आइसोलेशन में बदले 2500 कोच
» रोजाना औसतन 375 कोच में किया गया बदलाव

नईदिल्ली (आरएनएस)। कोविड 19 से पार पाने के प्रयासों में सहयोग देने के क्रम में भारतीय रेलवे अपनी पूरी ताकत और संसाधन लगा दिए हैं। इतने कम समय में उसने अपने 5,000 कोच को आइसोलेशन (एकांत) कोच में तब्दील करने के शुरुआती लक्ष्य में 2,500 कोच के साथ आधा लक्ष्य हासिल कर लिया है।

लॉकडाउन के दौर में जब कार्यबल संबंधी संसाधन सीमित बने हुए हैं और उनका समझ-बूझ से इस्तेमाल किया जाना जरूरी है, रेलवे के विभिन्न मंडल कार्यालयों ने इतने कम समय में असंभव से लग रहे इस कार्य को लगभग पूरा कर लिया है। लगभग 2,500 कोचों में बदलाव के साथ अब 4,000 आइसोलेशन बेड आपात स्थिति के लिए तैयार हैं।

एक बार नमूने को जैसे ही मंजूरी मिली, मंडल रेलवे कार्यालयों ने तेजी से बदलाव का काम शुरू कर दिया था। भारतीय रेलवे के रोजाना औसतन 375 कोचों में बदलाव किया जा रहा है। देश के 133 स्थानों पर यह काम किया जा रहा है। पूर्व में जारी किए गए चिकित्सा परामर्शों के तहत इन कोचों में सभी सुविधाएं हैं।

तब्लीगी मरकज़ से निकले लोगों की पहचान के लिए पुलिस ने निकाला फॉर्मूला

नईदिल्ली (आरएनएस)। देश की राजधानी दिल्ली समेत दूसरे शहरों की पुलिस लगातार तब्लीगी जमात से जुड़े लोगों की तलाश कर रही है. ये वो लोग हैं जो 15 मार्च से 28 मार्च तक मरकज़ में रुके या गए थे. ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए दिल्ली पुलिस ने नया तरीका निकाला है. मरकज़ के एरिया में इस दौरान एक्टिव रहे मोबाइल फोन नंबर का डाटा तैयार किया जा रहा है. इस लिस्ट में ऐसे नंबर शामिल किए जा रहे हैं, जो तीन से चार दिन तक मरकज़ में रुके हैं या वहां का एक चक्कर लगाया है. अगर शक के दायरे में आया नंबर दूसरे शहर और राज्य का है तो वहां की पुलिस को इसकी

सूचना दी जा रही है. यह कवायद कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की तलाश के लिए की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली समेत दूसरे शहरों की पुलिस लगातार तब्लीगी जमात से जुड़े लोगों की तलाश कर रही है. ये वो लोग हैं जो 15 मार्च से 28 मार्च तक मरकज़ में रुके या गए थे।

कोरोना के बारे में भ्रामक सूचना को तत्काल रोकना आवश्यक :नायडू

» उपराष्ट्रपति ने किसी भी समुदाय के बारे में निराधार पूर्वाग्रह न रखने की अपील की

नईदिल्ली (आरएनएस)। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को आगाह किया है कि वे अंध विश्वासों और सुनी-सुनाई बातों के बहकावे में, कोविड- 19 के विरुद्ध अपने संकल्प को कमजोर नहीं होने दे सकते। उन्होंने भ्रामक सूचना के प्रसार को, विशेषकर सोशल मीडिया द्वारा हो रहे प्रसार को, वायरस कहा जिसे तत्काल रोका जाना जरूरी है। अफवाहों और भ्रामक सूचना के प्रसार को रोकने के लिए, प्रामाणिक सूचना के निर्बाध प्रसार को जरूरी बताते हुए नायडू ने अपने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि यदि हम इस कठिन परिस्थिति की गंभीरता को सही तरह से नहीं समझ सकते, तो हम वायरस के विरुद्ध यह जंग नहीं जीत सकते। कुछ राज्यों में सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों के गैर जिम्मेदाराना उल्लंघन तथा नई दिल्ली में हाल में आयोजित समागम के संदर्भ में उपराष्ट्रपति ने दिशा निर्देशों के और व्यापक प्रसार तथा कड़ाई से पालन किए जाने की जरूरत को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि स्थिति की गंभीरता के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। वायरस संक्रमण के बारे में वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर, जात-पात क्षेत्र भाषा संप्रदाय से उपर उठ कर, एक समेकित प्रयास अपेक्षित है।

आरपीएफ दे रहा श्रमिकों को कोरोना से लड़ने का प्रशिक्षण

नईदिल्ली (आरएनएस)। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) दिल्ली में कोरोनावायरस संक्रमण रोकने के लिए पांच हजार से अधिक लोगों की मदद कर रही है। यह लोग ऐसे श्रमिक हैं, जो देशव्यापी लॉकडाउन के लागू होने के बाद दिल्ली से अपने-अपने राज्यों के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहे थे।

इन श्रमिकों को आरपीएफ न केवल दो वक्त का भोजन मुहैया करा रही है बल्कि इन्हें कोरोना को दूर भगाने के तरीके भी सिखाए जा रहे हैं। इसके साथ ही संक्रमण को रोकने के लिए आरपीएफ ने खुद सैनिटाइजर तैयार करके इन लोगों को दिए हैं। श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से कोरोनावायरस को परास्त करने का प्रशिक्षण भी रेलवे पुलिस दे रही है। दिल्ली में पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, निजामुद्दीन, आनंद विहार और सफदरजंग रेलवे स्टेशन के अलावा दिल्ली के आधा दर्जन छोटे, बड़े रेलवे स्टेशनों पर आरपीएफ ने निस्सहाय श्रमिकों के भोजन की व्यवस्था की है। गौरतलब है कि काम धंधे बंद होने के कारण श्रमिकों के समक्ष भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई है। श्रमिकों ने अपने-अपने गांव की ओर पैदल ही पलायन शुरू कर दिया था।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जरूरी मामलों पर सुनवाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। देशभर में कोरोना वायरस की कमर तोड़ने के लिए 21 दिनों का लॉकडाउन जारी है। ऐसे में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जरूरी मामलों पर सुनवाई कर रहे हैं।

शीर्ष अदालत ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा था कि वह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बेहद

जरूरी मामलों की सुनवाई करना जारी रखेगा। अदालत ने सोमवार को देश भर की सभी अदालतों के लिए दिशा-निर्देशों के लिए दिशा-निर्देश पारित किए। जिसमें न्यायिक कार्यवाही के लिए वीडियो-कांफ्रेंसिग का उपयोग करने कहा गया है। अदालत का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए वकीलों और वादियों की भीड़ को निलंबित कर दिया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने 25 मार्च लॉकडाउन की अवधि के दौरान अपने कामकाज को प्रतिबंधित कर दिया है और केवल बेहद जरूरी मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर रही है। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी उच्च शक्ति का प्रयोग करते हुए सभी उच्च न्यायालयों को महामारी के दौरान प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए एक तंत्र तैयार करने का निर्देश दिया।

पांच दिनों में 769 विदेशी पर्यटकों ने स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल पर कराया पंजीकरण

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच आवश्यक लॉकडाउन की स्थिति में देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की पहचान करने तथा उन्हें सहायता और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 31 मार्च 2020 को पोर्टल की शुरुआत की। सहायता प्राप्त करने के लिए ऐसे पर्यटकों को पोर्टल पर लॉग इन करना होगा, अपने संपर्क के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी देनी होगी और यदि कोई समस्या या कठिनाई है, तो उसके बारे भी बताना होगा। पोर्टल के शुरु होने के पहले पांच दिनों के भीतर ही देश भर से 769 विदेशी पर्यटक इसपर अपना पंजीकरण करा चुके हैं।

प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने ऐसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए एक नोडल अधिकारी बनाया है । पर्यटन मंत्रालय के पांच क्षेत्रीय कार्यालय , पोर्टल पर भेजे जाने वाले अनुरोधों के अनुरूप पर्यटकों को आवश्यक सहायता पहुंचाने के लिए इन नोडल अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय कर रहे हैं। विदेशी पर्यटकों के वीजा मुद्दों के संबंध में आव्रजन ब्यूरो और एफआरआरओ के साथ भी समन्वय बनाए हुए हैं। ऐस पर्यटकों को देश के अदंर किसी राज्य में भेजने या उनके देश वापस भेजने के अनुरोध पर विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय संबंधित देशों के दूतावासों / उच्चायोगों / वाणिज्य दूतावासों के साथ समन्वित रूप से काम कर रहे हैं।

पीएम और ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल के प्रधानमंत्री के बीच फोन पर हुई बातचीत

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल के प्रधानमंत्री महामहिम स्कॉट मॉरिसन के साथ टेलिफोन पर बात की। दोनों राजनेताओं ने वैश्विक महामारी कोविड-19 तथा इससे लड़ने के लिए दोनों देशों द्वारा किये जा रहे कार्यों और अपनाई गई रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया।

दोनों राजनेताओं ने इस स्वास्थ्य संकट के संदर्भ में आपसी सहयोग पर आधारित अनुसंधान के प्रयासों समेत द्विपक्षीय अनुभवों को साझा करने के महत्व पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार यात्रा प्रतिबंधों के कारण देश में फंसे ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को आवश्यक सुविधाएं व समर्थन प्रदान करने के लिए तैयार है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री मॉरिसन ने आश्वासन देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों समेत भारतीय समुदाय को ऑस्ट्रेलियाई समाज के जीवंत हिस्से के रूप में महत्व देना जारी रखा जाएगा।

लॉकडाउन के बाद पूरी तरह सील किए जाएंगे कई इलाके

» सर्वाधिक प्रभावित इलाकों की हो रही युद्ध स्तर पर पहचान » » मुंबई में दूसरे से तीसरे चरण के बीच पहुंची कोरोना महामारी

नई दिल्ली (आरएनएस)। आगामी 14 अप्रैल को जहां देश के कई हिस्सों को लॉकडाउन से कुछ कड़े शर्तों के बाद मुक्ति मिलेगी। वहीं कई इलाकों को एक विशेष अवधि तक पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा।

पूरी तरह सील होने वाले ऐसे इलाके होंगे जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी हो रही है। इसके लिए हॉट स्पॉट जगहों की युद्ध स्तर पर पहचान हो रही है। दरअसल पहली अप्रैल के बाद लगातार बिगड़ रही

स्थिति ने सरकार को चिंतित कर दिया है। नए महीने में संक्रमित होने वालों की संख्या प्रतिदिन 250 से बढ़ कर 600 के आंकड़े को पार कर गई। सरकार की मुख्य चिंता मुंबई है जहां हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। यहां 26 नर्सों और 4 डाक्टरों के कोरोना संक्रमित होने के बाद पूरे अस्पताल को भी क्वारंटाइन जोन घोषित कर दिया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि जहां फिलहाल भारत के अन्य हिस्सों में कोरोना अपने दूसरे चरण में है, वहीं मुंबई में यह दूसरे और तीसरे चरण के बीच आ गया है।

यहीं सबसे ज्यादा कम्युनिटी ट्रांसफर के मामले आए हैं। सूत्रों का कहना है कि वर्तमान में देश के करीब 280 जिलों में कोरोना प्रवेश कर गया है। इनमें करीब चार दर्जन जिलों में हालत ज्यादा खराब है। सरकार 14 अप्रैल तक इन सभी जिलों की स्थिति पर नजर रख रही है। इसी दिन पूरी हो रही लॉकडाउन के अवधि के बाद उन जिलों-इलाकों को चिन्हित किया जाएगा जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे इलाकों को 15 अप्रैल से बफर जोन घोषित कर पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। जिन इलाकों को सील किया जाएगा वहां कर्फ्यू जैसी स्थिति बहाल होगी। लोगों को आवश्यक सामान घर पर ही पहुंचाया जाएगा।

मेडिकल उपकरण खरीदने गौतम गंभीर देंगे 1 करोड़

नईदिल्ली (आरएनएस)। क्रिकेटर से राजनेता बने गौतम गंभीर ने कोरोना महामारी से बचाव के उपायों खासकर मेडिकल उपकरण खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपये देने की पेशकश की है. दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस बारे में खत लिखकर कहा है कि उन्होंने दो हफ्ते पहले 50 लाख रुपये दिल्ली सरकार को देने का संकल्प किया था. उन्होंने खत में लिखा है कि मैं 50 लाख रुपये सांसद निधि से भी देने का संकल्प करता हूं उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने यह बयान दिया था कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में उपकरणों की कमी को पूरा करने के लिए फंड की दरकार है. इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए मैं सांसद कोटे से 50 लाख रुपये देने का संकल्प दोहराता हूं।